Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre

ISSN: 2582-2004
Volume 05, Issue 02

DOI: 10.46523/jarssc.05.02.16
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

आधुनिक भारत में सामाजिक, राजनैतिक सुधार

शांति भूषण सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास) सर्वोदय पी.जी. कॉलेज, सलोन रायबरेली।

यह शोध पत्र आधुनिक भारत में हुए सामाजिक एवं राजनैतिक सुधारों की सामान्य समीक्षा करता है। इन सुधारों ने भारत को एक समावेशी, समानतापूर्ण एवं लोकतांत्रिक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय असमानताएं सदियों से रही हैं, वहां पर सामाजिक और राजनीतिक सुधार आवश्यक और अनिवार्य रहे हैं। इस शोध पत्र में स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात की सामाजिक परिस्थितियों, सुधार आंदोलनों, संवैधानिक उपायों, समकालीन चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना –

यह अत्यंत गर्व की बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक भूखंड पर संसार की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ जिससे मानव सभ्यता के विकास की कहानी को समझने में आसानी होती है मानव विकास की कहानी केवल रेखीय अथवा वृत्तीय ना होकर सभी ज्यामितीय अंकों के अतिरिक्त भी है भारतीय भूखंड में पुष्पित एवं विकसित सभ्यता की अनेक विशेषताएं हैं इन विशेषताओं में विविधता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है यहां अनेक धर्मो, जातियों, भाषा समूहों और परंपराओं का संगम दिखाई देता है। इसके विपरीत भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, लिंगीय असमानता, धार्मिक कट्टरता, छुआछूत एवं विविध प्रकार के भेदभाव जैसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं। जिनके परिमार्जन एवं सुधार के प्रयास भी सभी कालखंड में देखने को मिलता है। प्राचीन समय में हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का विकास भारतीय समाज का एक सुधारात्मक पहलू है। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन, सूफीवाद ने भी भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, भ्रष्टाचारों, अनैतिक विश्वासों आदि पर कुठाराघात करने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन के दौरान इस तरह की सामाजिक समस्याओं ने और भी अधिक विकराल रूप धारण किया जिसे अंग्रेजों ने अपने हित लाभ के अनुरूप इसका भरपूर प्रयोग किया। किंतु ब्रिटिश शासन के दौरान प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित सुधारको एवं मनीषियों ने आधुनिक काल में भारतीय समाज में व्याप्त इन कुरीतियों को परिमार्जित करने का भरपूर प्रयास किया। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण में इन विविध राजनीतिक एवं सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों को निराकृत करने का सार्थक प्रयास किया गया।

Received: 01.11.2022 **Accepted:** 13.12.2022 **Published**: 14.12.2022

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 05, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.05.02.16
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

जैसे–जैसे कोई समाज या राष्ट्र प्रगति के पथ पर चलता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने भीतर की कमियों को समझे तथा इसे दूर करे। यह प्रगति अथवा विकास का लक्षण है। भारत का समाज प्राचीन काल से ही विविधताओं से युक्त रहा है। अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम होते हुए भी यह समाज जातिगत भेदभाव, लिंग असमानता, धार्मिक कट्टरता आदि समस्याओं से ग्रस्त रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान इन समस्याओं ने और भी विकराल रूप ले लिया। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण में इन आदर्शों को समाहित किया गया और अनेक सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों की शुरुआत हुई।

1. सामाजिक सुधारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आधुनिक भारत में सामाजिक सुधारों की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। यह वह समय था जब पश्चिमी शिक्षा, तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच का प्रवेश भारत में हो रहा था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और 'आत्मीय सभा' तथा 'ब्रम्ह समाज' की स्थापना की। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर उदार वायसराय लार्ड विलियय बेंटिंक द्वारा कानूनी रोक लगी। 'ईश्वरचंद्र विद्यासागर' ने विधवा विवाह को वैध बनाने के लिए संघर्ष किया और बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम–1856 उन्हीं के प्रयास से पास हुआ।

आर्यसमाज की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने की। आर्यसमाज वैदिक परम्पराओं में विश्वास करता है, यह मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्म काण्ड, अंधविश्वास, छुआछूत और जातिगत भेदभाव का विरोध करता हे। यह आन्दोलन हिन्दू धर्म पर पाश्चात्य संस्कृत के बढ़ते प्रभाव के विरूद्ध एक प्रक्रियावादी आन्दोलन था। इसका मूल नारा ''वेदों की ओर लौटो था''। आर्यसमाज ने शिक्षा द्वारा समाजसुधार और राजकीय आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभायी। स्वदेशी आन्दोलन, हिन्दी सेवा, विशेषतः देवनागरी का विकास आर्यसमाज की प्रमुख उपलब्धियाँ रही है।

ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य दलित एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रसार तथा उनके सामाजिक अधिकारों में सुधार लाना था। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को प्रथम शिक्षिका के रूप में याद किया जाता है। सत्य शोधक समाज ने ब्राम्हणीय व्यवस्था पर चोट करते हुए गैर ब्राम्हण आन्दोलन को गहराई से प्रभावित किया, जिसका प्रभाव दलित आन्दोलनों एवं किसान आन्दोलनों में देखा जा सकता है। केरल में श्री नारायण गुरू द्वारा ऐझवा समुदाय के लोगो के बीच आन्दोलन किया गया, इसमें अछूतोंद्धार एवं मन्दिर प्रवेश की माँग की गयी।

Received: 01.11.2022 **Accepted:** 13.12.2022 **Published**: 14.12.2022

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 05, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.05.02.16
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

यह समाज सुधार केवल हिन्दू वर्ग में नहीं हुआ अपितु मुस्लिम समुदाय में भी वहाबी, फराईजी, अहमदिया एवं अलीगढ़ आन्दोलन द्वारा मुस्लिम समाज में व्याप्त धार्मिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव, एवं कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। अलीगढ़ आन्दोलन ने भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार मुस्लिम पर्दाप्रथा, बहुपत्नी प्रथा, तलाक जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास किया। अलीगढ़ आन्दोलन के प्रणेता सर सय्यद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम आंग्ल विद्यालय की स्थापना की, जो चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना तथा अलीगढ़ मुस्लिम आन्दोलन का गढ़ बन गया।

महात्मा गांधी ने छुआछूत को 'अधर्म' कहा तथा दलितों के लिए हरिजन शब्द का सम्बोधन प्रारम्भ करते हुए उनके मंदिर प्रवेश, जलस्रोतों तक पहुँच और सामाजिक समानता की वकालत की। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने न केवल दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया, अपितु भारतीय संविधान का निर्माण कर उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की।

2. स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख सामाजिक सुधार

भारत के संविधान ने भारतीय नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, मातृत्व, पंथनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का अधिकार दिया। अनुच्छेद 14 से 18 विशेष रूप से सामाजिक समानता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता हुआछूत जैसी घृणित मानसिकता को समाप्त कर दिया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए दहेज निषेध अधिनियम (1961), बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, च्वै॰ अधिनियम (2013) जैसे कानून बनाए गए। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के माध्यम से महिला कल्याण को बल मिला। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, और हाल की नई शिक्षा नीति 2020 ने शैक्षणिक असमानताओं को दूर करने की कोशिश की है।

3. राजनितिक सुधार और लोकतंत्र की मजबूती

भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु कई महत्त्वपूर्ण राजनैतिक सुधार किए गए हैं। चुनाव प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM VPAT), और चुनावी खर्च सीमा जैसे उपाय किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों में वृद्धि ने निष्पक्ष चुनाव को संभव बनाया है। RTI अधिनियम (2005) ने जनता को सूचना का अधिकार दिया जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ा।

Received: 01.11.2022 **Accepted:** 13.12.2022 **Published**: 14.12.2022

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 05, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.05.02.16
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

लोकपाल अधिनियम (2013) भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम था, किन्तु इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न भी हैं। अभी इसे अधिक प्रभावी एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता है। 73वाँ और 74वाँ संशोधन अधिनियम पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है, जिससे गाँधी जी के आदर्श, स्थानीय स्वराज को मजबूती मिली है। महिलाओं को पंचायतों और नगरीय निकायों में 33% आरक्षण देने से जमीनी स्तर पर महिलाओं में नेतृत्व का विकास हो रहा है। इससे पर्दा प्रथा, लिंगीय असमानता आदि आदि कुरीतियों को भी समाप्त करने में मदद मिल रही है।

4. समकालीन चुनौतियां

हालांकि देश ने सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर कठिन चुनौती का सामना करते हुए लंबी दूरी तय की है, लेकिन कई समस्याएं अब भी गंभीर रूप में विद्यमान हैं। जिन्हें दूर उसे की आवश्यकता है। जातिवाद आज भी ग्रामीण समाज में गहरी पैठ बनाया हुआ है। दलितों के विरुद्ध हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि, लड़कियों से छेड़छाड़, लैंगिक असमानता, तथा कार्यस्थलों पर यौन शोषण की शिकायतें आना आम बात हो गयी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सुविधाओं में भारी असमानता है। भारतीय राजनीति में वंशवाद, जातिवाद, धनबल और बाहुबल का बोलबाला है। विधायकों की खरीद–फरोख्त और दल–बदल, दंगा–फसाद, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नुकसान पहुँचाना लोकतंत्र की आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं। साम्प्रदायिकता, फेक न्यूज, और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से सामाजिक सौहार्द पर खतरा मंडराता रहता है।

5. भविष्य की दिशा और संभावनाएं –

भारत के पास एक विशाल युवा जनसंख्या है जो देश के भविष्य का नव निर्माण कर सकती है। सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। जिसमे नई शिक्षा नीति 2020, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। ई–गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और पहुँच तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों, और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए विशेष योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं।

स्थानीय शासन को और अधिक शक्तिशाली और उत्तरदायी बनाने का प्रयास हो रहा है ताकि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर सफल हो सके। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और तकनीक के समावेश से भारत सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक समावेशी और उत्तरदायी बन रहा है।

Received: 01.11.2022 **Accepted:** 13.12.2022 **Published**: 14.12.2022

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 05, Issue 02
DOI: 10.46523/jarssc.05.02.16
Multidisciplinary, Open Access
Impact Factor: 3.575

निष्कर्ष –

आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनैतिक सुधारों की यात्रा सतत्, जटिल और बहुआयामी रही है। संविधान ने इस यात्रा को दिशा प्रदान की, लेकिन उसकी सफलता का श्रेय केवल सरकारी नीतियों से नही अपितु जन सहभागिता, नैतिक उत्थान, शिक्षा से संभव है। यदि नागरिक समाज, युवा शक्ति और शासन मिलकर कार्य करें, तो भारत को एक विकसित, न्यायसंगत, समतामूलक, और लोकतांत्रिक देश बनाना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि सुधारों की भावना केवल कागजों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी परिलक्षित हो।

सन्दर्भ–ग्रन्थ

1– एन0 फर्कहार – मार्डन रिलीजियस अमेण्ड्स न इण्डिया

2– विपिन चन्द्र – आधुनिक भारत का इतिहास

3– शिवनाथ शास्त्री – हिस्ट्री ऑफ रिनेशा

4– जे0टी0एफ0 गार्डन – दयानन्द सरस्वती

5– वी0ो0 नरायन – सोसाल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया

6– पारेख मनिहाल – ब्रह्म समाज

7– एम0जी0 रानाडे – रिलीजियस एण्ड सोसल रिफार्मस

Received: 01.11.2022 **Accepted:** 13.12.2022 **Published**: 14.12.2022

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.